जापान प्रदेश में 11 हजार करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को तैयार

जापान की सरकार के सहयोग से औद्योगिक शहर बसाने का प्रस्ताव

अभिषेक गुप्ता

- शहर के साथ-साथ विदेशी कंपनियां भी करेंगी निवेश
- निवेश की इच्छुक कंपनियों के साथ पहले ही एमओयू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर ने जापान जैसे देश को भी आकर्षित किया है। 65 देशों में फैले जापान के दिग्गज समूह मरुबेनी कॉरपोरेशन ने भारत में 'नेक्स्ट जेनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क' बनाने का प्रस्ताव रखा है। समूह ने केवल इंडस्ट्रियल पार्क ही नहीं बल्कि लगभग 11 हजार करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने का ऑफर भी दिया है। ये एफडीआई जापान की कंपनियों से आएगा। जापान से एफडीआई का इतना बड़ा ऑफर प्राप्त करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। ये शुरुआत 'भारत-जापान निवेश संवर्धन साझेदारी' के तहत जापान के एफडीआई के विस्तार के रूप में की गई है। 32 अरब डालर (2700 अरब रुपये लगभग) का मरुबेनी कॉरपोरेशन समूह चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम में औद्योगिक पार्क विकसित कर चुका है।

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक माहौल और सेक्टोरल नीतियां दुनियाभर के देशों का ध्यान खींच रही हैं। प्रदेश में 'नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल पार्क' विकसित करने का प्रस्ताव जापानी सरकार के सहयोग से मरुबेनी कॉरपोरेशन ने दिया है। इस संबंध में समूह ने जून में औद्योगिक विकास विभाग के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया है। इसमें एक पार्क से 40 हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार, प्रदेश की जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) में दो अरब डालर की बढ़ोतरी और लगातार एफडीआई की गारंटी दी गई है।

नेक्स्ट जनरशन पार्क

- मल्टीनेशनल कंपनियों की जरूरत के हिसाब से होगा विकसित।
- 24 घंटे बिजली-पानी-सुरक्षा।
- सौ फीसदी ईको फ्रेंडली।
- अंडरग्राउंड सुविधाएं व हरे-भरे मैदान स्काडा सिस्टम के तहत।
- शहरी और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, रहने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ श्रमिकों के लिए शानदार आवास।

सरकार से मांगा है ये सहयोग

- इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन।
- नीतियों के तहत इंसेंटिव।
- जल्द से जल्द जमीन।
- फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन।

प्रस्तावित परियोजना में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, एयरोस्पेस व रक्षा और फार्मा क्षेत्र में गारंटीड एफडीआई लाने का प्रस्ताव दिया गया है। खास बात ये है कि भारत में विस्तार करने की इच्छुक कंपनियों के साथ पहले ही समझौता हो चुका है। जापान की कंपनियां प्रदेश में 2800 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और 8000 करोड़ रुपये का अन्य निवेश करेंगी। निवेश की इस परियोजना को जापान के इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री मंत्रालय (मेटी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) और जापान एक्सटर्शन ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इन पार्कों के लिए तकनीकी कौशल से युवाओं को दक्ष करने के लिए विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों से एमओयू भी किया जाएगा।